**International Journal of Humanities and Social Science Research**
**www.socialsciencejournal.in**
**ISSN: 2455-2070**
**Received: 09-09-2025, Accepted: 09-10-2025, Published: 24-10-2025**
**Volume 11, Issue 5, 2025, Page No. 164-168**

# प्राथमिक शाला में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार के लिए विभिन्न रणनीतियां पर शोध

**बलदाऊ सिंह श्याम**
सहायक शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय प्राथमिक शाला, जमुनाही तिलकडीह, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

**सारांश**
प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश की शैक्षिक प्रणाली की आधारशिला होती है। इस स्तर पर बच्चों में पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही कौशल आगे की शिक्षा तथा जीवन के समग्र विकास का आधार बनते हैं। भारत में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (Foundational Literacy and Numeracy — FLN) को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें निपुण भारत मिशन (2021), समग्र शिक्षा अभियान, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP–2020) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा पढ़ने और गणना करने की न्यूनतम अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर ले। इस शोध में यह पाया गया कि आधारभूत साक्षरता और अंकज्ञान की समस्या मुख्यतः ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिक गहराई से विद्यमान है। इसका कारण प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षण सामग्री का अभाव, भाषा संबंधी बाधाएँ, तथा घर–विद्यालय के बीच संवाद की कमी है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं, जैसेकृ सक्रिय एवं बालक–केंद्रित शिक्षण पद्धतियाँ, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम, तकनीकी उपकरणों (ICT) का उपयोग, मल्टीलिंगुअल दृष्टिकोण, और समुदाय की भागीदारी। शिक्षक प्रशिक्षण को भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। शोध के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाती है, बल्कि यह बच्चों में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और समस्या–समाधान क्षमता का भी विकास करती है। यदि प्राथमिक स्तर पर साक्षरता और अंकज्ञान की मजबूत नींव रखी जाए, तो भविष्य में ड्रॉपआउट दरों में कमी, रोजगार योग्यता में वृद्धि, और राष्ट्र की समग्र प्रगति संभव है। अतः यह आवश्यक है कि नीति निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के सामूहिक प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और परिणाममुखी बनाया जाए।

**मूलशब्द:** आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक कौशल, निपुण भारत मिशन, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षण रणनीतियाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बालक–केंद्रित अधिगम ।

## प्रस्तावना
शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। बाल्यावस्था मानव जीवन का सबसे संवेदनशील और निर्माणशील चरण होता है, और इसी अवस्था में दी गई शिक्षा व्यक्ति के चरित्र, बुद्धि, विचार, तथा व्यक्तित्व की दिशा तय करती है। प्राथमिक शिक्षा इस प्रक्रिया की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्राथमिक शाला वह स्थान है जहाँ बच्चे औपचारिक शिक्षा की शुरुआत करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान, कौशल, और मूल्यों का अधिग्रहण करते हैं। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (जैसे जोड़–घटाव, गुणा–भाग आदि) किसी भी बच्चे की शिक्षण यात्रा की बुनियाद होते हैं। यदि ये कौशल प्राथमिक विद्यालय (ग्रेड 1–5) की शुरुआत में अच्छी तरह विकसित नहीं हुए, तो आगे की पढ़ाई, मनोवैज्ञानिक विकास, आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता और उच्च शिक्षा की संभावना प्रभावित होती है। भारत जैसे बड़े, विविध और असमानताओं से भरे देश में, साक्षरता–संख्यात्मकता की कमी गहरी समस्या है: उदाहरण के लिए ASER रिपोर्ट्स में दिखता है कि कई बच्चे कक्षा 3 में Grade–2 का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं या Grade–1–2 के अंकगणित के मूल भागों में कमजोर हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 ने इसे प्राथमिकता दी है, और NIPUN Bharat Mission की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य 2025–26 तक प्रत्येक बच्चे में Foundational Literacy and Numeracy (FLN) लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

'प्राथमिक शाला' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है – 'प्राथमिक' अर्थात् प्रारंभिक या आरंभिक, और 'शाला' अर्थात् विद्यालय या शिक्षण स्थल। इस प्रकार, प्राथमिक शाला का अर्थ है – वह शैक्षणिक संस्था जहाँ बच्चों को प्रारंभिक या आरंभिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा में 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः कक्षा 1 से 5 तक होती है। यह स्तर बालकों को भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कला, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की बुनियादी शिक्षा प्रदान करता है। विभिन्न शिक्षाविदों ने प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है –

1. **महात्मा गांधी के अनुसार** — "प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है – बालक को अपने परिवेश के अनुकूल, आत्मनिर्भर और नैतिक जीवन जीने योग्य बनाना।"

2. **रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा** — "प्राथमिक शिक्षा बालक के भीतर छिपी सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करने का साधन है।"

3. **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मतानुसार** — "प्राथमिक शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर राष्ट्र की संपूर्ण शैक्षणिक इमारत खड़ी होती है।"

इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शाला केवल ज्ञान प्रदान करने का केंद्र नहीं है, बल्कि यह बालक के सर्वांगीण विकास की आधारभूमि है।

## प्राथमिक शाला का उद्देश्य
प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना–लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि बालक को जीवन के प्रति सजग, आत्मनिर्भर और नैतिक

दृष्टिकोण से दृढ़ बनाना है। इस स्तर की शिक्षा का मूल लक्ष्य बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है ताकि वह समाज में एक जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक के रूप में स्थापित हो सके। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालक में मूलभूत साक्षरता एवं अंकज्ञान का विकास किया जाता है, जिससे वह पढ़ने, लिखने और गणना करने में दक्ष बन सके। इसके साथ ही, सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि बालक सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन और समाज में सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कला सीख सके। नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें ईमानदारी, करुणा, और नैतिकता जैसे मूल्यों का समावेश कराया जाता है। शारीरिक विकास के लिए खेलकूद, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे बालक का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे। इसी प्रकार, सृजनात्मक विकास के लिए कला, संगीत, नाटक और हस्तकला जैसी गतिविधियों के माध्यम से उसकी कल्पनाशक्ति और सृजनशीलता को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण चेतना का विकास भी आवश्यक है ताकि बालक प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास के प्रति संवेदनशील बने। अंततः, राष्ट्रीय एकता एवं नागरिकता भावना का निर्माण किया जाता है, जिससे बालकों में देशप्रेम, नागरिक कर्तव्यों की समझ और विविधता में एकता का भाव दृढ़ हो सके। इस प्रकार, प्राथमिक शिक्षा बालक के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की मजबूत नींव रखती है।

## प्राथमिक शाला का महत्व

प्राथमिक शाला का महत्व व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सभी स्तरों पर अत्यंत व्यापक है।

### 1. व्यक्तिगत स्तर पर महत्व

प्राथमिक शाला का महत्व व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत गहरा और व्यापक होता है, क्योंकि यही वह अवस्था है जब बालक के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास की नींव रखी जाती है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा इस अवधि में बालक के व्यक्तित्व को सही दिशा देने का कार्य करती है। यह शिक्षा बालक में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जिज्ञासा का विकास करती है, जिससे वह स्वयं पर विश्वास करना और अपने अनुभवों से सीखना प्रारंभ करता है। प्राथमिक शिक्षा बालक को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे वह चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करने में सक्षम बनता है। इसके अतिरिक्त, यह शिक्षा बुनियादी योग्यता और बौद्धिक कौशलों का विकास करती है, जो आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए मजबूत आधार बनते हैं। इस प्रकार, प्राथमिक शिक्षा बालक के व्यक्तित्व निर्माण की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जो उसे एक सशक्त, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर करती है।

### 2. सामाजिक स्तर पर महत्व

समाज की उन्नति और प्रगति सुशिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है, और इस दिशा में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक शिक्षा समाज में साक्षरता दर को बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग ज्ञान और जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकें। यह शिक्षा समानता, सहयोग और सहिष्णुता के भाव को जन्म देती है, जिससे समाज में आपसी समझ, सौहार्द और एकता को बल मिलता है। प्राथमिक शालाओं में बालकों को एक साथ पढ़ने और सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना विकसित होती है। इसके साथ ही, यह शिक्षा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को कम करने में सहायक होती है। शिक्षित व्यक्ति तर्कसंगत सोच अपनाता है और सामाजिक सुधार का माध्यम बनता है। इस प्रकार, प्राथमिक शालाएँ समाज में नैतिकता, समानता और भाईचारे के संस्कारों को प्रोत्साहित कर एक सशक्त, जागरूक और प्रगतिशील समाज की नींव रखती हैं।

### 3. राष्ट्रीय स्तर पर महत्व

राष्ट्र की उन्नति का मूल स्रोत उसकी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली होती है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर देश के विकास की संपूर्ण संरचना टिकी होती है। सुशिक्षित नागरिक किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं, जो अपने ज्ञान, कौशल और विचारों से समाज और देश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। प्राथमिक शिक्षा नागरिकों में ज्ञान और समझ का विकास कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के योग्य बनाती है। यह शिक्षा आर्थिक प्रगति, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षित समाज ही समानता, न्याय और सहयोग के सिद्धांतों को समझता और अपनाता है। साथ ही, प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी सोच का बीज बोती है, जिससे नवाचार और विकास की संभावनाएँ बढ़ती हैं। स्वतंत्र भारत में संविधान के अनुच्छेद 21(A) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा के महत्व को न केवल सामाजिक बल्कि संवैधानिक स्तर पर भी मान्यता देता है। इस प्रकार, प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की प्रथम और सबसे सशक्त कड़ी है।

### 4. वैश्विक स्तर पर महत्व

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG–4) में "सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा जीवनभर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना" एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत या राष्ट्रीय विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता की प्रगति और वैश्विक समृद्धि की आधारशिला है। प्राथमिक शिक्षा इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह बच्चों को ज्ञान, मूल्यों और कौशलों की वह बुनियाद प्रदान करती है, जिसके आधार पर वे आगे चलकर समाज और विश्व के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से सामाजिक असमानताओं में कमी आती है, गरीबी घटती है और सतत विकास की दिशा में ठोस प्रगति होती है। इस प्रकार, प्राथमिक शिक्षा न केवल किसी एक राष्ट्र के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व समुदाय के संतुलित और स्थायी विकास की आधारभूत आवश्यकता है।

## आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल के सुधार हेतु रणनीतियाँ

भारत तथा भारत जैसे विकासशील देशों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) के सुधार के लिए अनेक रणनीतियाँ और नवाचार लागू किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर तक, पढ़ने, लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता हासिल कर सके। सबसे पहले, शिक्षक क्षमता निर्माण (Teacher Professional Development & Capacity Building) की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। Language and Learning Foundation

(LLF) ने सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD) कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों, मेंटर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया है ताकि कक्षा में FLN–आधारित शिक्षण व्यवहार सुधारा जा सके। इसी प्रकार Central Square Foundation (CSF) ने "tructured pedagogy", "assessment&informed instruction (AII)", "professional training" और "mentoring" को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है। शोधों में पाया गया है कि यदि शिक्षकों को खेल–आधारित, बहुभाषिक और व्यवहारिक (hands–on) शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण दिया जाए, तो साक्षरता और संख्यात्मकता में उल्लेखनीय सुधार देखा जाता है।

दूसरा, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का पुनर्रचना (Curriculum & Pedagogy Innovations) भी एक प्रमुख रणनीति रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने " Foundational Stage" की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें ECCE (Early Childhood Care & Education) और कक्षा I–II को शामिल किया गया है, ताकि प्री–स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा के बीच सहज संक्रमण हो सके। खेल–आधारित शिक्षण (play&based learning), सहभागितापूर्ण शिक्षा, छोटे समूहों में गतिविधियाँ, और कहानी, गीत, नाटक आदि के माध्यम से सीखना, जैसे STRIPES2 प्रोजेक्ट (Madhya Pradesh) में अपनाए गए तरीके, बच्चों में FLN कौशल सुधारने में प्रभावी पाए गए हैं। इसी के साथ, मातृभाषा में शिक्षा देना कृ जैसा कि NEP और विभिन्न शोधों (जैसे Chaifry) ने सुझाया है — बच्चों की समझ और रुचि दोनों को बढ़ाता है।

तीसरा, मापन, आंकलन और निगरानी (Assessment, Monitoring & Data–Driven Practice) के क्षेत्र में भी सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं। Central Square Foundation ने " assessment–informed instruction" लागू किया है, जहाँ शिक्षक बच्चों के वर्तमान सीखने के स्तर को समझकर उसी के अनुरूप शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं। NIPUN Bharat Mission के अंतर्गत राज्यों और जिलों में FLN लक्ष्यों, मापदंडों और समय–सीमाओं को निर्धारित किया गया है, जिससे नियमित प्रगति रिपोर्टिंग और मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। विद्यालयों में छोटे–छोटे परीक्षणों (formative assessments) के माध्यम से भाषण, लेखन और गणना की नियमित जाँच की जाती है, ताकि मध्य–पाठ सुधार (midcourse correction) किया जा सके।

चौथा, संसाधनों का समुचित प्रावधान (Learning Materials – School Resource) भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Language and Learning Foundation (LLF) के कार्यक्रमों में किताबें, कार्यपत्रक, विजुअल एड्स और खेल–संबंधी सामग्री की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। इसी तरह Sampark Smart Shala जैसी परियोजनाओं ने स्कूलों को ऑडियो–विजुअल टूल्स, कहानी–पुस्तकें और शिक्षण खिलौने उपलब्ध कराए हैं, जिससे कक्षा को अधिक रोचक और व्यावहारिक बनाया जा सके।

पाँचवाँ, अतिरिक्त शिक्षण और सहायता (Remedial/ Supplementary & After–School Support) की रणनीति भी अत्यंत प्रभावी मानी गई है। प्रथम (Pratham) संगठन का "Teaching at the Right Level (TaRL)" मॉडल इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें बच्चों को उनके वर्तमान सीखने के स्तर के अनुसार समूहों में विभाजित कर, उसी स्तर के अनुरूप शिक्षण कराया जाता है। यह पद्धति विशेषकर संख्या ज्ञान और पठन कौशल सुधारने में कारगर सिद्ध हुई है।

छठा, पारिवारिक एवं समुदाय सहभागिता (Parental & Community Engagement) भी FLN सुधार की एक प्रमुख कड़ी है। STRIPES2 प्रोजेक्ट में यह देखा गया कि बच्चों के सीखने में माताओं और देखभाल करने वालों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। माता–पिता–शिक्षक बैठकें, घर पर पठन–पाठन, कहानी सुनाना, पुस्तकालय उपयोग और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना बच्चों की सीखने की रुचि को बढ़ाते हैं।

सातवाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (Early Childhood Care and Education – ECCE) और "स्कूल प्रारंभ तैयारी मॉड्यूल" की अवधारणा ने भी बुनियादी साक्षरता में सुधार किया है। NEP 2020 में ECCE को शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा माना गया है ताकि बच्चे विद्यालय में प्रवेश से पहले ही भाषा, रंग, आकार, और संख्या की समझ विकसित कर सकें। इसके लिए ग्रेड–1 के बच्चों के लिए तीन महीने का School Preparation Module" भी सुझाया गया है।

आठवाँ, भाषा नीति और बहुभाषिक शिक्षा (Language Policy & Multilingual Instruction) की दृष्टि से मातृभाषा–आधारित शिक्षा को अत्यधिक प्रभावी पाया गया है। जब बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा दी जाती है जिसे वे घर पर बोलते हैं, तो उनकी समझ, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। शिक्षा सामग्री और पुस्तकें स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने तथा भाषा–उत्सव और पठन अभियानों के माध्यम से इसे प्रोत्साहित किया जा सकता है।

नवाँ, प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान (Technology & Digital Tool) आज के युग में शिक्षण का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। GraphoLearn या GraphoGame जैसे डिजिटल टूल्स बच्चों को अक्षर–ध्वनि संयोजन सिखाने में मदद करते हैं, जो साक्षरता सुधार के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसी तरह DIKSHA, Sampark Smart Class और अन्य EdTech प्लेटफॉर्म्स ने दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच बढ़ाई है।

**अंततः,** नीति और मिशन स्तर की पहल (Policy & Mission Level Interventions) के तहत NIPUN Bharat Mission को एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में 2025–26 तक FLN लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लागू किया गया है। राज्यों और जिलों में FLN को योजना, बजट और संसाधनों में प्राथमिकता दी जा रही है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में NIPUN Mission के तहत शिक्षक और विद्यालयों के लिए पुरस्कार प्रणाली शुरू की गई है ताकि उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मिले।

## मामले / उदाहरण

**STRIPES2, मध्यप्रदेश:** इस कार्यक्रम में छोटे–समूह, घरों और स्कूलों में गतिविधि–आधारित शिक्षण, आई–माताओं / माताओं की भागीदारी आदि शामिल थीं। यह देखा गया कि बच्चों का पढ़ने–समझने और अंकगणित कौशल में सुधार हुआ।

- **भाषा और लर्निंग फाउंडेशन (LLF):** इसके कार्यक्रमों ने दस राज्यों में काम किया है; लाखों बच्चों और शिक्षकों तक पहुँचे हैं; प्रशिक्षण, जिले–स्तरीय प्रदर्शनी एवं संसाधन निर्माण के माध्यम से FLN प्रथाओं को स्कूल प्रणालियों में शामिल किया है।

- **Central Square Foundation (CSF):** ASER Report के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ग्रामीण भारत में कक्षा–3 के बहुत से छात्र Grade–2 का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं और गणना में भी पिछड़े हैं; CSF ने इस स्थिति को सुधारने के लिए नीतिगत अभियान, शिक्षण–पाठ्यक्रम संशोधन एवं मूल्यांकन–आधारित शिक्षण प्रचालाएँ लागू की हैं।

## चुनौतियाँ

भारत में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के सुधार की दिशा में अनेक पहलें की गई हैं, परंतु इनके सफल क्रियान्वयन में कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या शिक्षक

की कमी और उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ी है, क्योंकि अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है और जो शिक्षक हैं, उन्हें मातृभाषा–आधारित शिक्षण, गतिविधि–आधारित या remedial शिक्षण जैसी विशेष FLN–पद्धतियों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त भाषाई विविधता और भाषा–माध्यम की समस्या भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, क्योंकि बहुत से बच्चों की मातृभाषा शिक्षण भाषा से भिन्न होती है, जिससे वे अवधारणाओं को ठीक से समझ नहीं पाते, और साथ ही स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें या संसाधन प्रायः उपलब्ध नहीं होते। संसाधनों और अवसंरचना की कमी भी एक बड़ी बाधा है — अनेक विद्यालयों में पुस्तकें, वर्कबुक्स, श्रवण–दृश्य सामग्री, शिक्षण उपकरण, स्वच्छता और भवन जैसी बुनियादी सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही बच्चों की अनियमित उपस्थिति, ड्रॉपआउट दर और सामाजिक असमानताएँ (विशेष रूप से लड़कियों, दलित, आदिवासी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में) समस्या को और जटिल बनाती हैं। COVID–19 जैसी आपदाओं ने इस learning loss को और बढ़ाया है। मापन एवं निगरानी की प्रणाली में भी खामियाँ हैं, क्योंकि आंकलन प्रायः केवल सत्र समाप्ति पर होता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में समय रहते सुधार संभव नहीं हो पाता। डाटा–संग्रह, रिपोर्टिंग और कार्यवाही की प्रक्रिया भी धीमी और निष्क्रिय रहती है। अंततः नीति और वित्तीय चुनौतियाँ भी प्रमुख अवरोध हैं—कई बार बजट की सीमाएँ, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन न होना शिक्षा–गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अतः इन चुनौतियों को समग्र दृष्टिकोण से संबोधित करना आवश्यक है, ताकि FLN लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

## आगे की रणनीतियाँ एवं सिफारिशें

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु अनेक रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं, जिनमें प्रारंभिक वर्षों (ECCE व कक्षा I–II) पर विशेष ध्यान देना शामिल है, जैसे स्कूल तैयारी मॉड्यूल लागू करना और ECCE कार्यक्रमों को मजबूत बनाना ताकि बच्चों में भाषा, संख्यात्मकता व मोटर कौशल का विकास हो सके; मातृभाषा–आधारित शिक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें शिक्षण माध्यम मातृभाषा हो और शिक्षक उसी भाषा में दक्ष हों; आंकलन एवं प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय करना, जिसमें समय–समय पर Formative व Diagnostic मूल्यांकन, कमजोरियों की पहचान कर remedial सत्र, और पारदर्शी प्रगति निगरानी शामिल हो; शिक्षक प्रशिक्षण व समर्थन के लिए निरंतर पेशेवर विकास और मेंटरिंग की व्यवस्था; स्थानीय भाषा में किताबें, कहानी–पुस्तकें, खेल–आधारित सामग्री, पुस्तकालयों का विकास और डिजिटल संसाधनों की समानुपात पहुँच सुनिश्चित करना; अतिरिक्त शिक्षण सहायता जैसे छुट्टियों में remedial क्लासेस, ट्यूटरिंग व पियर–ट्यूशन; पारिवारिक व सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जिसमें माता–पिता को शिक्षण में सहयोगी बनाना और समुदाय में पढ़ने की आदतें बढ़ाना; प्रौद्योगिकी व नवाचार का उपयोग जैसे गेम–आधारित लर्निंग, मोबाइल एप्स, blended learning मॉडल और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता; तथा नीति व मिशन स्तर पर समर्थन जैसे NIPUN Bharat Mission को पर्याप्त बजट व नियंत्रण देना, स्थानीय संदर्भ अनुसार योजनाएँ बनाना और शिक्षण गुणवत्ता, शिक्षक अनुपात व भाषा नीतियों में सुधार हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना शामिल हैं।

## संभावित परिणाम और लाभ

यदि उपर्युक्त रणनीतियाँ प्रभावी रूप से लागू की जाएँ, तो प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की पाठ समझने की क्षमता और अक्षर–संख्या ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है, जिससे पढ़ने–समझने और गणना में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा; साथ ही ड्रॉप–आउट दर में कमी आएगी और लिंग, क्षेत्र तथा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर असमानता घटने की सम्भावना बनेगी; इससे विद्यालयों की समग्र गुणवत्ता और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होगा, जो आगे की शिक्षा—माध्यमिक और उच्चतर स्तर—के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करेगा।

## निष्कर्ष

भारत में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल सुधारने के लिए NEP 2020 और NIPUN Bharat Mission जैसे बड़े सरकारी प्रयास, NGOs और शिक्षा–संस्थाओं द्वारा प्रमाणित कार्यक्रम, और शोधों द्वारा सुझाई गई प्रायोगिक विधियाँ पहले से मौजूद हैं । इन रणनीतियों का सफल क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि नीति से व्यवहार तक कैसे बदलाव लाया जाए:

- स्थानीय संदर्भों की समझ हो,
- भाषा, संसाधन, प्रशिक्षण आदि में सुविधा हो,
- निगरानी और अनुकूलन हो,
- समुदाय और परिवार की भागीदारी हो।

यदि ये शर्तें पूरी हों, तो भारत में प्राथमिक शालाओं में साक्षरता–संख्यात्मकता की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और हर बच्चे को शिक्षा के पहले कदमों में मजबूत आधार मिल सकता है।

## संदर्भ ग्रंथ


1. Government of India, Ministry of Education. National Education Policy 2020. New Delhi: Government of India, 2020. https://www.education.gov.in/nep2020 (n.p.)
2. Gandhi MK. Naitik Shiksha aur Buniyadi Taleem Moral education and basic learning. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1953, 45–78.
3. Tagore R. Shiksha aur Manavata Education and humanity. Santiniketan: Visva-Bharati Publications, 21–56.
4. Radhakrishnan S. Bhartiya Shiksha Darshan Philosophy of Indian education. Delhi: Oriental Publishing Company, 1952, 10–34.
5. Srivastava SK. Bhartiya Shiksha ka Itihas aur Darshan [History and philosophy of Indian education]. Lucknow: Prakashan Sansthan, 2016, 101–130.
6. Mishra R. Prathamik Shiksha ke Siddhant Principles of primary education. Delhi: Lajpat Rai Publications, 2018, 55–98.
7. National Council of Educational Research and Training NCERT. Prathamik Shiksha mein Shikshan Adhigam ki Prakriya Learning processes in primary education. New Delhi: NCERT, 2014, 12–44.
8. Kumar A. Shiksha Manovigyan aur Shikshan Vidhiyan Educational psychology and teaching methods. Jaipur: Aruna Publications, 2019, 89–120
9. Government of India, Ministry of Human Resource Development. Sarva Shiksha Abhiyan: Final Report 2015–2020. New Delhi: MHRD, 2020, 1–60.
10. UNICEF. Primary Education in India: Status and Challenges. New York: UNICEF Publications, 2021, 5–48.
11. Government of India, Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. New Delhi:

Government of India. https://www.education.gov.in/nep2020
12. National Council of Educational Research and Training NCERT. Nipun Bharat: Foundational Literacy and Numeracy Mission Guidelines. New Delhi: NCERT, 2021, 1–65.
13. UNICEF. Foundational Learning and Numeracy in India: Status and Strategies. New York: UNICEF Publications, 2020, 12–54.
14. Kaul V. Early Childhood Education in India: Quality and Inclusion. New Delhi: Oxford University Press, 33–80.
15. Banerjee A, Duflo E. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: PublicAffairs, 2011, 102–145.
16. Srivastava SK. Bhartiya Shiksha ke Aadhar: Prathmik Star ke Chunautiyan aur Samadhan Foundations of Indian Education: Challenges and Solutions at the Primary Level. Lucknow: Prakashan Sansthan, 2018, 89–120.
17. National Sample Survey Office NSSO. Education in India: Status, Challenges and Policy Response. New Delhi: Government of India Press, 2019, 45–98.
18. Kumar R. Prathmik Shiksha mein Gunvatta Sudhar ke Naye Aayam New Dimensions of Quality Improvement in Primary Education. Jaipur: Aruna Publications, 15–70
19. Pratham Education Foundation. ASER Report 2022: Annual Status of Education Report. New Delhi: Pratham, 2022, 5–60.
20. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All, 2020. Paris: UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718